राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
35वीं बैठक - दिनांक : 22 नवम्बर, 2010 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सितम्बर, 2010 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 35वीं बैठक होटल साफ्टल प्लाजा, सहारनपुर रोड, देहरादून में दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को आयोजित की गई।

इस बैठक में श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) एवं आयुक्त (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन, श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन, श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, श्री वी.एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री बी. के. बंसल, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, श्री विजेन्द्र शर्मा, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राकेश पुरी, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

माननीय डा. रमेश पोखरियाल '' निशंक '', मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का संबोधन -

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य की स्थापना के समय से अब तक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात लगभग ढाई गुणा वृद्धि कर 54.04 % तक पहुँच गया है, जोकि एक सराहनीय प्रयास है। परंतु राज्य के पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात अब भी औसत से बहुत कम है जिस पर सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने **जिलों की ऋण-जमा अनुपात** की समीक्षा करते हुए कहा कि **नैनीताल जिला** का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है और जिसे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। आयुक्त (कुमायुँ) को इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु नैनीताल के जिलाधिकारी, जिला स्तर के संबंधित विभाग, नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि प्रदेश को आयुष राज्य बनाने हेतु जड़ी-बूटी के कृषिकरण एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश के नैसर्गिक पर्यावरण सौगात के रुप में प्राप्त जड़ी-बूटियों का यथोचित दोहन करने की आवश्यकता है। अब तक **प्रदेश में जड़ी-बूटी के उत्पादन हेतु 18,000 इच्छुक कृषकों को जोड़कर कुल ` 20 करोड़** की जड़ी-बूटी का विपणन किया जा रहा है। इसी क्रम में निदेशक, जड़ी-बूटी ने मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया कि पिछले वर्ष 62 नर्सरी स्थापित की गईं थीं और इस वर्ष 65 नई नर्सरी स्थापित करने का लक्ष्य है।

इस संबंध में एक कोर ग्रुप का गठन किया जाएगा जिसमें गैर-सरकारी संगठन (NGOs) / स्वयं सहायता समूहों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो नर्सरी से पौधे दिलाने से लेकर उनकी देख-रेख और मूल्य परिवर्धन (Value addition) कर विपणन की व्यवस्था भी करेंगें।

उन्होंने उत्तराखंड राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए साहसिक एवं धार्मिक पर्यटन की ओर पूरे विश्व को आकर्षित करने की दिशा में विशेष कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया कि इस वर्ष चमोली जिले के **'' ओंली ''** में विश्व शीतकालीन खेलों का अयोजन किया जा रहा है। अतः पर्यटक / यात्रा मार्गों पर प्रदेश की महत्वाकांक्षी **'' वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना** '' के अंतर्गत सर्व सुविधा सम्पन्न होटल एवं रेस्टोरेंट स्थापित करने तथा अन्य संबंधित उद्योग / व्यवसाय की वृद्धि हेतु पर्यटन विभाग एवं बैंक अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों के ग्रामीण विकास विभाग, नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ बैठक कर, **अटल आदर्श ग्राम** के लिए अलग से वार्षिक विकास योजना बनाएं और इन योजनाओं को प्रत्येक अटल आदर्श ग्राम में समावेशित करें। इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण (Monitoring) ब्लाक स्तर पर गठित कोर कमेटी द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री महोदय ने बैंकों द्वारा आरसेटी की स्थापना हेतु एफ.आर.डी.सी. विभाग को निर्देशित किया कि शेष **सात जिलों में (टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर व चम्पावत**) उचित भूमि उपलब्ध कराएं और संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को कहा कि वह जिलाधिकारी के साथ बैठक कर एक सप्ताह के अंदर चयनित भूमि को आरसेटी के पक्ष में हस्तांतरित करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने खेद प्रकट करते हुए **निदेशक (उद्योग) को निर्देशित किया कि एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड** की पिछली दो बैठकों के कार्य बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई है। प्रत्येक जिले के लिए कम से कम दो क्षेत्र विशेष योजना बनाकर बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करें। उन्होंने आगे कहा कि जिन पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात औसत से कम है उन्हें भी स्थानीय कच्चा माल आधारित छोटे-छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) को भी योजना तैयार कर बैंकों से वित्तपोषित करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

श्री सुनील पंत, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए बैठक में पधारे सभी बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों का अभिनन्दन किया और राज्य के विकास में उनके योगदान पर आभार प्रकट किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 35वीं बैठक में सभी बैंकों द्वारा सितम्बर, 2010 की समाप्ति तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठकों से संबंधित कार्य बिंदुओं में से कई मुद्दों पर कार्य किया गया है और अभी कुछ पर कार्य करना है।

उन्होंने भारत सरकार के (नीतिगत) दूरस्थ गाँवों तक वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा वैकल्पिक माध्यम (Alternate Channel) से बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु किए जा रहे कार्यों से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में एक उप महाप्रबंधक (आउटरीच) के नए पद पर नियुक्त किया गया है जिसका कार्य ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के निर्बल वर्ग के निवासियों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए किस प्रकार वैकल्पिक बैंकिंग प्रणाली का विकास किया जाए ।

उन्होंने कहा कि सितम्बर, 2010 में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 54.04 % तक पहुँच गया, जो एक उल्लेखनीय प्रगति का द्योतक है, परंतु कुछ बैंक जैसे कि **यूको बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया** आदि जिनकी शाखाओं की संख्या राज्य में समुचित हैं और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों के कुल ऋण में ` **3,947 करोड़** का ऋण राज्य से बाहर स्थित बैंक शाखाओं का है, यदि इसमें से कुछ ऋण राज्य में स्थित शाखाओं द्वारा दिया जाए तो प्रत्यक्ष ऋण-जमा अनुपात में अच्छी वृद्धि हो सकती है और यह राज्य में स्थित बैंक शाखाओं के लिए व्यवसाय वृद्धि करने में एक अच्छा अवसर हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष बैंकों के लिए **वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य ` 5915.41 करोड़** के सापेक्ष ` **2618.05 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गई है, जोकि द्वितीय त्रैमास तक के लिए निर्धारित, भारतीय रिजर्व बैंक के 40 % मानक से 4 % अधिक, **यानि** 44 % है। इस उपलब्धि को बैंकों द्वारा और अधिक बढ़ाया जा सकता है। जिन प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है उन्हें अब शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयास करने होंगे।

राज्य के सभी **अटल आदर्श ग्रामों एवं 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों** को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने की प्रक्रिया में सभी बैंक त्वरित गति से कार्यवाही करें, ताकि मार्च, 2011 तक शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त कर उत्तराखंड राज्य देश में प्रथम स्थान पर आ सके। भारतीय स्टेट बैंक ने 5 जिलों में ग्रामवासियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु **उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी (UPASaC)** को नया बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट नियुक्त किया है. इसके लिए उन्होंने सरकार एवं बी.एस.एन.एल. से अनुरोध किया कि सभी अटल आदर्श ग्रामों में ब्रॉड बैण्ड / जी.पी.आर.एस. सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें।

सात जिलों (टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर व चम्पावत) में आरसेटी हेतु आवासीय भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित भूमि आवंटित / हस्तांतरित की जानी है। ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता और ऋण प्रदान करनेहेतु सभी जिलों पर संबंधित बैंकों द्वारा एफ.एल.सी.सी. स्थापित की गई है, परंतु यह सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रहा है और इस पर बैंकों को सुधार लाने की आवश्यकता है। सभी बैंक अपने कार्य क्षेत्र में ऋण (Credit) प्रदान करने, वित्तीय समावेशन, नए उद्योग स्थापित करने के बीच आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर

एस.एल.बी.सी. की उप-समिति की बैठक में समाधान पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की योजनांतर्गत बैंकों को ` 1 करोड़ तक के कोलेट्रल फ्री औद्योगिक ऋण की प्रगति संतोषजनक है, बैंकों को यह ऋण और अधिक से अधिक संख्या में ऋण प्रदान करने चाहिए।

उन्होंने कहा कि **मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना** के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक ने उद्यान विभाग के सहयोग से विभिन्न जड़ी-बूटियों के कृषिकरण हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें कृषकों के लिए वित्तमान (Scale of finance) भी निर्धारित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक एवं हर्बल रिसर्च एवं विकास संस्थान (HRDI), गोपेश्वर आज एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक व राज्य सरकार जड़ी-बूटी उत्पादन में तीव्रता लाने हेतु विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में बैठक के अंत में माननीय मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल '' निशंक '' एवं भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील पंत की उपस्थिति में एक '' **मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग ''** (MoU) का आदान-प्रदान और जड़ी-बूटी से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उद्यान विभाग द्वारा **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में संरक्षित खेती करने के लिए, बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने हेतु बैंकपरक प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहे हैं। राज्य में पॉली हाऊस स्थापित करने हेतु उद्यान विभाग ने 750 इच्छुक कृषकों को बैंक ऋण लेने हेतु चयनित किया है।उन्होंने उद्यान विभाग को सुझाव दिया है कि ऋण प्राप्ति से पूर्व कृषकों को पॉली हाऊस संरक्षित खेती संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

बैंकों के गैर निष्पादित अस्तियों की वसूली हेतु दायर ऋण वसूली प्रमाण पत्रों पर वसूली की प्रगति बहुत धीमी है। सभी बैंक वसूली के लिए अंतिम प्रयास के रुप में यह प्रक्रिया प्रयोग में लाते हैं, इसलिए शासन से अनुरोध ही नहीं, बल्कि अपेक्षा है कि वसूली प्रक्रिया में गति लाकर बैंकों के एन.पी.ए. को कम करने में सहयोग करें ताकि उपयुक्त ऋणियों को ऋण देने में बैंकों का मनोबल बढ़े।

अंत में, उन्होंने सबका धन्यवाद करते हुए अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन का संबोधन ः

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि वित्तीय समावेशन से संबंधित उत्तर भारत के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय के साथ चंडीगढ़ में बैठक हुई थी। इस बैठक में माननीय डा. रमेश पोखरियाल, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में वित्तीय समावेशन के संबंध में 2000 से अधिक आबादी वाले गाँव का मानक व्यवहारिक नहीं है बल्कि यहाँ गाँवों की दूरी के अनुसार मानक निर्धारित करने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में बैंकों द्वारा 1 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करने का वार्षिक लक्ष्य है तथा इसी क्रम में निदेशक (कृषि) को निर्देशित किया कि आगामी दो वर्षों में एक विशेष अभियान चला कर सभी पात्र कृषकों को के.सी.सी. उपलब्ध कराने में बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

इसी परिप्रेक्ष्य में नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्रतिनिधि ने प्रश्न उठाया कि प्राइवेट बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋणों पर सरकार द्वारा 2 % ब्याज में छूट (Interest Subvention) देने का प्रावधान नहीं है जिस के लिए शासन से अनुरोध है कि उचित कार्रवाई करें।

श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव (पर्यटन) का संबोधन ः

प्रमुख सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन ने सभी बैंकों को आश्वस्त किया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 30 सितम्बर, 2010 तक सभी लम्बित अनुदान राशि 30 नवम्बर, 2010 तक बैंकों को प्रेषित कर दी जाएगी और भविष्य में बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर मासिक अंतराल में पर्यटन विभाग द्वारा अनुदान राशि प्रेषित कर दी जाएगी। उन्होंने बैंकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सभी लम्बित आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरित कर दें और यदि किसी प्रकरण पर व्यवधान हो तो उसे जिला स्तरीय बैठकों में चर्चा कर शीघ्र निस्तारित करें, क्योंकि अब अनुदान मिलने में कोई विलम्ब नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को विकसित करने की दृष्टि से प्रदेश में नए-नए क्लस्टर चयनित किए हैं जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लगाने का ब्यौरा तैयार किया गया है, जिसकी कुल लागत ` 150 करोड़ आने की संभावना है। इस आशय की सूची बैंकों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि इस पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इससे बैंकों को ऋण देने के क्षेत्र में नए विकल्प प्राप्त होंगे।

अंत में मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश को आयुष राज्य बनाने में बैंकिंग क्षेत्र का पहला कदम उठाने पर भारतीय स्टेट बैंक की सराहना की, जिसके अंतर्गत 7 जड़ी-बूटियों के कृषिकरण हेतु बनाई गई बैंकपरक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पुस्तिका का विमोचन किया। प्रदेश में जड़ी-बूटी विकास करने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक एवं हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंन्ट इन्स्टीट्यूट (HRDI), गोपेश्वर के बीच मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग (MoU) का आदान-प्रदान किया गया।

सभा के अंत में **श्री राकेश पुरी, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली** द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं बैठक में राज्य सरकार एवं बैंकों से पधारे शीर्ष अधिकारियों का आभार प्रकट किया और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरुप कार्य निष्पादित करने हेतु सभी बैंकों की ओर से आश्वसन दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक की ओर से सभी बैंक अधिकारियों को आगामी बैठक हेतु दिसम्बर, 2010 तक के सही एवं पूर्ण आँकड़ों के विवरण दिनांक 20 जनवरी, 2011 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करने हेतु आग्रह किया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****